

were high. And the Government of India took a decision to reduce the prices three or four times; during the last six or eight months the off-take has been increasing. During the rabi season, the off-take increases by 25 per cent. The stocks that we are having, we are deliberately holding them up for the reason that as far as the domestic manufacturers are concerned they should not hold up their stocks. We have got full stocks, imported stocks, and we are encouraging the local manufacturers to dispose of their stocks. That is our approach in regard to the increase of domestic production.

श्री श्रीउम प्रकाश त्वाणी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपके मंत्रालय को इस बात का ज्ञान है कि जो रासायनिक खाद के बजाए गोबर खाद जो कि भारतवर्ष में बहुत बड़ी तादाद में है और उसका दुरुपयोग किसान, चूँकि लकड़ी नहीं है इसलिए रोटी खादि बनाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं, तो क्या उस गोबर खाद का ईंधन के रूप में इस्तेमाल न हो, वह खाद के काम में आये, इस विज्ञा में आपने कोई उपाय सुझाये है ?

SHRI ANNASAHIB P. SHINDE : In fact, for the last two years a very large number of subsidised gobar gas plants have been put up. Just now, the number is almost 20,000 and we propose to have at least one lakh. Ultimately, the organic resources which are available in the country have to be used for the development of our agriculture. But I think there has to be an effective combination of both inorganic and organic fertilisers. That helps agriculture very much. Therefore we have to lay emphasis on utilising our local resources, at the same time not neglecting the development of any organic fertiliser. That is broadly our approach.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : In view of the fact that raw materials like water, air and electricity are available in abundance in the hilly areas, will the hon. Minister be pleased to say what specific

steps are being taken to encourage the production of more and more fertilisers through the electrolysis process so that we need not depend on any imports ?

SHRI ANNASAHIB P. SHINDE : I can reply to the question, but it will be more proper if the hon. Member puts this question to the Ministry of Fertilisers.

MR. CHAIRMAN : Next question .

#### Sick Sugar Mills in U.P.

\*183. SHRI R. NARASIMHA REDDY +

SHRI IBRAHIM KALANIYA :  
SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ :

SHRI JAGDISH JOSHI :

SHRI KHURSHED ALAM KHAN :

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether any of the sugar mills in Uttar Pradesh are likely to be declared as sick mills;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether there is any proposal under Government's consideration even to take over those sugar mills which are running as viable units at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) No such proposal is under consideration at present.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

The question was actually asked on the floor of the House by Shri R. Narasimha Reddy.

SHRI R. NARASIMHA REDDY : May I know from the hon. Minister whether it is the policy of the Government to take over all the sick concerns in the country? This will be a sort of premium on mismanagement and I think it is not a correct policy to take over all the sick mills. May I know the opinion of the hon. Minister?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : Sir, we deal with each individual case on its merits. The primary consideration before us is that the mills must function, the production should not be affected, the growers should not suffer and the labour who work in the mills should not also suffer. So in the interest of the growers and the labourers, we have sometimes to take over mills which are not functioning very efficiently.

SHRI R. NARASIMHA REDDY : Sir, in view of the difficult position of the sugar mills all over the country, there has been a consideration by the Government to nationalise all the sugar mills in the country. Has the Government taken a decision regarding this matter?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : Sir, the hon. Member is aware that the Sugar Industry Enquiry Committee has submitted its report. That report is receiving the consideration of the Government as far as nationalisation is concerned.

**श्री इब्राहीम कलानिया :** मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल मालिकों ने पिछले तीन वर्षों में कितनी कमाई की है और उसका कितने प्रतिशत उन्होंने मिलों के रख-रखाव में खर्च किया है? प्रश्न के उत्तर से ऐसा लगता है कि चीनी मिल-मालिकों की लापरवाही से ही ये मिलें निकम्मी साबित हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मिल-मालिक मिलों को चलाने की जिम्मेदारी सरकार पर थोपना चाहते हैं उस जिम्मेदारी के लिये मिल-मालिकों के प्रति सरकार का क्या रुख है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

**श्री शाहनवाज खां :** जैसा मैं पहले कह चुका हूँ जो मिल्स किसी कारण से सही तौर से काम नहीं

करती हैं, गवर्नमेंट को इसमें स्टेप-इन करना पड़ता है ताकि हम उन मिलों को किसी तरह से चला सकें। हरेक मिल ने कितना कमाया है इसके पूरे आंकड़ें मेरे पास नहीं हैं। जो मेरे पास इन्फार्मेशन है उसके मुताबिक मिल-मालिक यह कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कमाया है। हम घाटे में रहे हैं।

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : Will the hon. Minister be pleased to state whether it is possible for him to consider that more and more of the sick mills should be converted into co-operative mills so that a larger number of people in the rural areas can share in the production of sugar?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : The policy is to give more licences to the co-operative sector for setting up new factories. But to convert old junks into cooperative mills would not be proper.

**श्री जयदीश जोशी :** श्रीमान्, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में जो चीनी मिलें हैं वे मिलें दक्षिण भारत की चीनी मिलों के उत्पादन से कम उत्पादन करती हैं। इस तथ्य को सामने रखते हुए क्या शुगर मंत्रालय उन्हें बीमार की स्थिति में नहीं मानता? यदि नहीं मानता है तो कम से कम इतना तो मानता है कि उत्पादन कम होता है? ऐसी स्थिति में उनका सहकारीकरण या उनकी मशीनों के रेणलडाइजेशन की कोई योजना सरकार के पास है ताकि नई मशीनें आ सकें और उत्पादन की गति को बढ़ाया जा सके।

**श्री शाहनवाज खां :** पहली बात तो यह है कि मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो हमारी नाथं इण्डिया की शुगर मिलें हैं उनमें रिकवरी और उत्पादन किसी तरह से साउथ इंडिया की मिलों से कम हैं क्योंकि जो हमारा शुगरकैन रिसर्च सेंटर लखनऊ में है उसने यह साबित कर दिया है कि इनके उत्पादन और रिकवरी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इतना फर्क

जसर है कि हमारी जो मिलें नार्थ इण्डिया में हैं वे 30-35 साल से भी ज्यादा उम्र की हो चुकी है और वे बहुत जईफ हो चुकी हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि उन्हें बदला जाय, तबदील किया जाय। गवर्नमेंट के सामने रिहैविलिटेशन एण्ड मोड्रेनाइजेशन आफ ओल्ड मिल्स की एक स्कीम है जो कि सरकार के विचाराधीन है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही इस सिलसिले में काम शुरू हो जाएगा।

**SHRI KHURSHED ALAM KHAN :** It is a fact that the uncertainty about the future of the sugar industry in U.P. continues in spite of the report which has been submitted by this committee. In the first instance, I would like to know whether it is a unanimous report or there is difference<sup>5</sup> of opinion in the committee regarding the basic policy of nationalisation. I would also like to know whether it is a fact that this year the production of sugar will be less by about four to five lakh tonnes as compared to the production last year, and this is attributable, on the one hand, to the mill owners who have tried to depress production and, on the other hand, to the cane growers who were not able to get good prices and who, therefore, diverted their cane to khandsari factories.

**SHRI SHAH NAWAZ KHAN :** Sir, regarding the question of nationalisation, there was no unanimity in the committee which was set up to go into the matters of the sugar industry. In fact, it was equally divided; five members were of one view and five members were of another view. Regarding the production of sugar this year, I agree that the production of sugar this year would be substantially less than what it was last year. There are many factors which are responsible for it. There was heavy rainfall and water-logging, and sugarcane production suffered. Also, Sir, the crushing of the sugarcane started very much later this year I than it used to start in the earlier years.

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि चीनी मिलों को

नेशनलाइज करने के बारे में विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है, लेकिन इस संबंध में सरकार कोई निर्णय इसलिए नहीं ले सकी कि इस कमेटी के पांच सदस्य एक तरफ थे और पांच सदस्य दूसरी तरफ। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट आए कितने दिन हो गये हैं और अभी तक इस संबंध में सरकार ने निर्णय क्यों नहीं लिया है? क्या नेशनलाइज करने के संबंध में निर्णय न लेने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि कुछ निजी उद्योगपतियों और मिल-मालिकों का इस प्रकार का दबाव है जिसके कारण इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा अभी आपने कहा कि बहुत-सी मिलें बहुत ज्यादा जईफ हो चुकी हैं उनके मोड्रेनाइजेशन का प्रोग्राम है, तो क्या कोई प्रायोरिटी मुकदर की गई है कि इतने समय के अन्दर इन मिलों का मोड्रेनाइजेशन किया जाना चाहिए? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन शुगर मिलों को सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जैसे बिजनौर, अमरोहा और सबौलीटोडा आदि स्थानों में जो मिलें हैं उनमें पहले जितनी रिकवरी होती थी, क्या यह सही है कि अब सरकार के हाथ में आने के बाद इन मिलों में रिकवरी घट गई है? क्या यह भी सही है कि किसानों का जो पैसा इन मिलों की ओर था वह भी ज्यादा बढ़ गया है?

**श्री शाहनवाज खां :** ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत-सी मिलें इस तरह की हैं जहां पर गवर्नमेंट के टेकओवर के बाद रिकवरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मैं चलेन्ज तो नहीं करता, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अमरोहा की जो मिलें सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं उनमें पहले क्या रिकवरी थी और आज रिकवरी क्या है?

श्री शाहनवाज खाँ : आप रोहता कलाँ की हालत देख लीजिये। अलग अलग एरियाज की मिलों की अलग अलग स्थिति है। यह भी ठीक नहीं कि चूँकि इन्कवायरी कमेटी के मेम्बर्स बराबर दलों में बंट गये थे, इसलिए गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं कर सकी है। असल में सरकार के सामने विचार करने की बात यह है कि इस वक्त हम नेशनलाइज करके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर सकते हैं या नहीं, और प्रोडक्शन में किसी तरह की रुकावट न हो। इन सब चीजों पर हमें विचार करना है और यह भी देखना है कि किस तरह से प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय।

लेकिन जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको देखते हुए क्या हम उनको कंपेंसेशन दे सकते हैं? अगर हम नेशनलाइज करते हैं तो जो इम्प्लेज्मेंटो ट्रेन्ड्स थे, जो बढ़ती हुई कीमतें थीं, उनको जिस तरह हमने रोका है, क्या वह फिर से, दोबारा, बे लगाम नहीं हो जायगी? ये सवाल भी हमारे सामने हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति महोदय, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। मेरा प्रश्न तो यह है कि नेशनलाइजेशन के बारे में कमेटी की रिपोर्टें दिए हुए 2 साल से ज्यादा हो गए। मेरा कहना यह है कि वह तबबार उनके ऊपर लटकी हुई है और अब वे पैसा नहीं लगा रहे हैं और खचड़ा मिलों को चला रहे हैं; रिक्वरी कम हो रही है। आप यह तो कहिए कि नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे या नेशनलाइजेशन करेंगे ताकि मिलों का माडर्नाइजेशन हो जाए। यह बीच की स्थिति क्यों चली हुई है?

श्री शाहनवाज खाँ : यह तबबार लटकने से पैदावार कम हो गई यह बात नहीं है क्योंकि पिछले साल हमने ऑल टाइम रिकार्ड 48 लाख टन चीनी की पैदावार हानिल की थी। इससे जाहिर है कि तबबार के लटकने से पैदावार कोई कम नहीं हुई है और नेशनलाइजेशन का फैसला गवर्नमेंट खुद लेगी जब गवर्नमेंट को सूट करेगा।

SHRI GIAN CHAND TOTU : May I know from the honourable Minister whether it is a fact that the operational cost of some of the sick mills taken over by the Government has increased enormous-ly causing huge losses?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN : It J varies from mill to mill. Some mills have I done very well and others, because of I certain inherent defects, have not done so well. They have done as well or as badly as the general sugar industry itself, in the country.

श्रीमती सविता बहिन : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि यह गवर्नमेंट के एक्टिव कंसिडरेशन में पिछले कई सालों से है कि शुगर मिल्स को नेशनलाइज किया जाए। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या सिक् मिल्स के बारे में ही यह रिपोर्ट है कि उनको नेशनलाइज किया जाय या सारे शुगर मिल्स के नेशनलाइजेशन के लिए है, और कब तक इस बारे में फैसला होगा।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि ये जो सिक् मिल्स इस तरह से लगातार पड़े हुए हैं, क्या उन्हें इसी तरह से चलते रहने से गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता है?

श्री शाहनवाज खाँ : मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूँ कि नेशनलाइजेशन के ऊपर फैसला गवर्नमेंट कब करेगी? यह गवर्नमेंट की अपनी सहूलियत के ऊपर है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के ऊपर है और गवर्नमेंट के विचार के ऊपर है। जैसा मैंने अर्ज किया कि प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स जो हम इस वक्त कर रहे हैं उसका जो महत्व है उसको कायम रखा जाए, उसमें कोई रुकावट नहीं हो। जो सिक् मिल्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल की सिक् मिल्स हैं, वैसे ही शुगर सिक् मिल्स जो हैं जिनका मैनेजमेंट सही तौर पर नहीं होता है, गवर्नमेंट को मजबूरन उनको लेना पड़ता है।

SHRI N. H. KUMBHARE : Sir, we have been told that the question is under the active consideration of the Govern-

ment and we would like to know whether the Government would take over those mills. My point is that the time factor in this is very important and if you take more time, then the sick mills would become worthless. Now, they are sick and they may later on succumb to their sickness and die. Therefore, before they die, you must take over them. I would like to know specifically from the honourable Minister whether it would be possible for him to specify the time by which the Government would take a decision on this. The Government may not take over all the mills; but it may take over some mills at least and it may start a few mills. So, [I would like to know from the honourable Minister when it would be possible for the Government to take over these mills.

**SHRI SHAH NAWAZ KHAN :** Sir, the policy of the Government is to help the sick mills to regain their health so that they can be rehabilitated and modernised. For that the Government is thinking of granting loans to them on easy terms.

**SHRI BRAHMANANDA PANDA :** Sir, sickness of a mill or a factory is not as sudden as the case of heart attack in a man. From ordinary indisposition to the state of being bed-ridden it is a long process. So, my question is fundamentally this: What preventive machinery does the Government have to see that such mills like the sick sugar mills and other mills, which are foreign-exchange-earners, do not fall sick often? And, Sir, if at all they fall sick, why should they fall sick? What is being done by the Government officials who are in charge of this subject?

**SHRI SHAH NAWAZ KHAN :** Sir, even the modern science has not been able to overcome the ravages of old age. Some of these mills are so old that something radical has to be done.

**श्री जगबीर सिंह :** श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो मिल्स इस समय गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उन मिलों के ऊपर किसानों की गन्ने की कीमत

की प्रदायगी की रकम बढ़ी है या घटी है? मैं मिसाल के तौर पर बुलन्दशहर की शूगर मिल्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब से यह मिल सरकार के हाथों में आई है तब से गन्ने की कीमत जो किसानों को मिलने चाहिये उनके एरीयर्स बढ़े हैं या घटे हैं?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक शूगर मिलों के नेशनलाइज करने का सवाल है, उस चीज को तब करने में सरकार को कितना समय लगेगा? आपका, इरादा इस संबंध में क्या है और क्या आप इन मिलों का नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं या नहीं? इस (बारे में) सरकार की राय कम से कम तो मालूम हो जानी चाहिये कि इन मिलों का नेशनलाइजेशन करना जरूरी है या नहीं? इतना तो मंत्री जी कम से कम बतला ही सकते हैं?

**श्री शाहनवाज खाँ :** मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूँ कि जब से हमने शूगर मिल्स ली हैं उस समय से लेकर पहले तनामुब तक पेमेंट की पोजीशन बहुत ख़राब रही है।

**श्री जगबीर सिंह :** आप बुलन्दशहर मिल की बात बतलाइये।

**श्री शाहनवाज खाँ :** मैं ओवरघाल यू०पी० की बात कर रहा हूँ और हर एक मिल की मेरे पास जानकारी नहीं है। पूरे यू०पी० की पोजीशन पिछले साल से इस साल बहुत ख़राब है। इसी टाइम में पिछले साल 16.5 परसेंट पेमेंट ओवर-ड्यूज थे और इस समय 3.2 परसेंट है जो कि पिछले साल का आधा है। मैं यह बात पिछले साल यू०पी० की कर रहा हूँ।

**श्री जगबीर सिंह :** क्या यह गवर्नमेंट के फ़िगर हैं?

**श्री शाहनवाज खाँ :** यह गवर्नमेंट के फ़िगर हैं जो फ़ैक्टरियों से मिले हैं।

**श्री जगबीर सिंह :** जिन मिलों का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हाथ में है, उनका क्या हाल है

श्री साहनबाज खाँ : उनका हाथ भी बहुत खरटा है ।

### **Damage to Forests by Animals**

\*184. SHRI GIAN CHAND TOTU :f

SHRI SYED NIZAM-UD-DIN :

SHRI NIRANJAN SINGH

TALIB:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether any assessment has been made recently with regard to damage caused to forests by animals, like goat etc.; and

(b) if so, what steps Government propose to take to safeguard the forests from such damage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHIB P SHINDE) : (a) No formal assessment of damage caused to forests by animals like goat etc. has been made but observations indicate that over grazing is harmful to the forests.

(b) Measures for safeguarding the forests from such damage are, however, undertaken by way of fencing suitable forest areas.

SHRI GIAN CHAND TOTU : May I know from the hon. Minister as to what specific measures have been taken in States like Himachal Pradesh or Jammu and Kashmir where forests are in abundance, to stop damage to forests as well as land erosion by goats ?

SHRI ANNASAHIB P. SHINDE : Sir, as I submitted in my reply, apart from goats—goats cause damage to grazing grounds and forest—there is over-grazing by other types of cattle which causes damage to forests. Though some reserved forests are there—of course, grazing is not allowed there—there are areas, unreserved

fThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Gian Chandel Totu.

forests. There the State Governments have arrangements, but they are not very satisfactory.

One of the basic reasons, I would like to inform the hon. Members, is that in India the population of cattle is really very high. Recently, the National Commission on Agriculture went into this. Our surface area is 2.2 per cent of that of the world while we have 19 per cent cattle of the world, 50 percent of the whole world's buffaloes. Again, the population of goats in the country is 18 per cent. This is an old figure of the world's population. We have increased our population of cattle by 55 millions over the last decade. So it is really the large number of unproductive cattle that is causing this damage. This is one of the reasons.

SHRI GIAN CHAND TOTU : May I know from the hon. Minister whether the Government is considering taking some steps for the replacement of goats by cows, because it is an established fact that the damage caused by goats is higher than that by other animals ? Has the Government considered this aspect of the situation ?

SHRI ANNASAHIB P. SHINDE : Sir, there have been recommendations by experts on this; we would like to take the House into confidence. It is a controversial subject. First of all, some people say that goat's milk is like mother's milk. Mahatma Gandhi used to take goat's milk, whether goats should be eliminated, it is a highly controversial thing. That is one thing.

Secondly, Sir, the goat is a poor man's cow. We do not graze goats openly. The poor people keep goats in their houses and they stall-feed them. What is necessary is to improve the system of feeding and not to destroy the goats. There is one additional factor. The stomach of goat is God's gift. It has tremendous capacity to digest any material. Also, our people eat mutton, etc. This is a highly controversial subject. Therefore, I cannot